



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

No. 70]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

निर्णायक समीक्षा

विषय: चीन और हांगकांग के मूल के या वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 15/30/2013- डी जी ए डी :- वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) चीन और हांगकांग (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं० 14/8/2008-डीजीएडी के तहत प्रकाशित की गई थी। जांच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 21 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं० 142/2009-सी.शु. के तहत संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

2. और यतः मै० जय श्रीराम टैक्सटाइल्स (आदित्य बिड़ला नवो लि० की एक इकाई) (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टीकृत आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे बढ़ाने और उसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

3. यह याचिका मै० आदित्य बिड़ला नवो लि० की एक इकाई मै० जय श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर की गई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई अन्य उत्पादक हैं अर्थात् मै० महेन्द्र कुमार एंड कं०, डोनियर इंडस्ट्रीज लि०, मणिराज सिंथेटिक्स, दर्शन क्रिएशन प्रा० लि०, महिन्द्रा टेक्सटाइल, गोवर्धन ओवरसीज प्रा० लि०, वी.पी. टेक्स प्रा.लि., वसंती फैब्रिक्स, वीएसएम वीव्स इंडिया लि० और वी.टी.एम. लि०, जिन्होंने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि मै० जय श्री टेक्सटाइल्स और उसके कंपनी समूह मै० मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल तथा मदुरा गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स लि० ने चीन से अल्प मात्रा में आयात किया है। अपने कंपनी समूह मै० मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल तथा मदुरा गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स के साथ-साथ मै० जय श्री टेक्सटाइल्स द्वारा किए गए आयात जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के उत्पादन के लगभग 3.31 प्रतिशत, कुल भारतीय उत्पादन के 1 प्रतिशत, संबद्ध देशों से कुल आयात के 4.93 प्रतिशत और भारत में मांग के 0.85 प्रतिशत बनते हैं। आयातों की कम मात्रा पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नियमों के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना गया है।

4. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और याचिका उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार संबंधी मापदंड को पूरा करती है।

विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल का या वहां से निर्यातित वोवन फैब्रिक (50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स तत्व वाला) है जिसे (आगे संबद्ध वस्तु) भी कहा गया है। "फ्लैक्स" और "लिनेन" समानार्थी हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनेन के रूप में भी जाना जाता है तथा इसका उपयोग फ्लैक्स फाइबर से निर्मित यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इसका अक्सर प्रयोग सामान्य तौर पर वोवन बैड, बाथ टब, टेबल और किचन टेक्सटाइल्स के वर्ग का वर्णन करने के लिए किया जाता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का व्यापक उपयोग टॉवलों और शीटों आदि के लिए किया जाता है। बोलचाल की भाषा में संबद्ध वस्तु का उल्लेख फ्लैक्स फैब्रिक के रूप में भी किया जाता है।

6. यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 53 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 53.09 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

7. चूंकि वर्तमान जांच इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में है।

समान वस्तुएं

8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान उत्पाद हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता दोनों को अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

शामिल देश

9. इस समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. और हांगकांग हैं।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य के निर्धारण का उपबंध है याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि तीसरे देशों में कीमत या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पाद लागत के आधार पर किया है। जहां तक हांगकांग का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि हांगकांग के घरेलू बाजार में संबद्ध उत्पाद की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। प्रकाशित स्रोतों से कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता हांगकांग के घरेलू बाजार में सौदा कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता हांगकांग के घरेलू बाजार में सौदा कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर हांगकांग के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

निर्यात कीमत

11. संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि समीक्षा जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भरत में पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता की सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने पाटित आयातों की अत्यधिक मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री और घरेलू उद्योग के लाभ, लगाई पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह के संबंध में अत्यधिक परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के रूप में आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। समीक्षा जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही सतत क्षति का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा

14. दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

जांच की अवधि

15. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से 30 सितंबर, 2013 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि पर 1 अप्रैल, 2010 से जांच अवधि की समाप्ति अर्थात 2010-11, 2011-12, 2012-13 तक और जांच अवधि के रूप में विचार किया गया है।

प्रक्रिया

16. इस समीक्षा में 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं0 14/8/2008-डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

17. इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश (शों) की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।

समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिन के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) के बारे में सूचित करें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए ।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादित परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है ।

26. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है या वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है । प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi the 10th March, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping duty concerning imports of Flax Fabrics origination in or exported from China and Hong Kong.

1. **F No. 15/30/2013-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Flax Fabrics from China and Hong Kong (hereinafter referred to as the subject countries). The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 14/08/2008-DGAD dated the 1st October, 2009. On the basis of the findings, anti dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 142/2009-Customs dated 21st December, 2009.

2. WHEREAS, M/s Jaya Shree Textiles (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.) (hereinafter referred to as the petitioner), have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, extension and modification of present form of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Jaya Shree Textiles, a unit of Aditya Birla Nuvo Ltd. There are a number of other producers of the product under consideration in India. Namely M. Mahendrakumar and Company, Donear Industries Limited, Muniraj Synthetics India Private Limited, Nirvan Silk Mills Private Limited, Balu Fabrics, Darshan Creation Private Limited, Mahindraa Textile, Master Linens, Govardhan Overseas Private Limited, V.P.Text Private Limited, Vasanthi Fabrics, VSM Weaves India Limited, and VTM Limited who have supported the petition. The petitioner has stated that M/s Jaya Shree Textiles and its group companies M/s Madura Fashion & Lifestyle and Madura Garments Exports Ltd has imported small quantities from China. Imports made by the M/s Jaya Shree Textiles along with its group companies M/s Madura Fashion & Lifestyle and Madura Garments Exports constitute approx 3.31% of petitioner's production, 1% of Total Indian production, 4.93% of total imports from subject countries and 0.85% of demand in India during the period of investigation. Considering low volume of imports, the petitioner has been considered as eligible domestic industry within the meaning of the Rules.

The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Product under Consideration

4. The product under consideration is Woven Fabric (having more than 50% Flax content), also refereed to (subject goods hereinafter) originating in or exported from China PR and Hong Kong. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is often used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. In common parlance subject goods are also referred as Flax fabric.

5. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at sub-heading 53.09. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

6. Since the current investigation is a Sunset Review investigation into anti-dumping duties currently in force, the scope of the products under consideration is the same as that in the original investigation.

Like Articles

7. The petitioner has claimed that the product produced by them is a like article to the product imported from the subject countries in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers use the two interchangeably. The subject goods produced by the petitioner is being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

Subject Countries

8. The country involved in this review investigation is China PR and Hong Kong

Normal value

9. The petitioner has claimed that China should be treated as a non-market economy country and the normal value should be determined in terms of Annexure I (7) of the AD Rules, which provides for determination of normal value in a non-market economy. Petitioner has claimed that normal value could not be determined on the basis of price or costs in third countries for the reason that no information is publicly available in this regard. Petitioner has determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India duly adjusted. In respect of Hong Kong Petitioners have submitted that efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Hong Kong. Efforts were also made to get any evidence of price from published sources. The petitioner has, however, not been able to get any evidence of transaction price in the domestic market of Hong Kong. In view of the same, the normal value has been constructed for all exporters/producers from Hong Kong, on the basis of cost of production in India, duly adjusted. The Authority has determined the normal value of subject goods in subject countries on the basis of cost of production in India, duly adjusted

Export Price

10. The export price has been determined from subject countries based on the import data provided by the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges and commission to arrive at the net export price.

Dumping Margin

11. The normal value of subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries continue to be dumped, to justify initiation of a review investigation.

Injury and Causal Link

12. Information of the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of significant volume of dumped imports, price undercutting, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the continued being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of a review investigation

Initiation of Sunset Review of Anti Dumping Duty

13. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

14. The Period of Investigation for the purpose of the present review investigation is 1st October, 2012 to 30th September 2013 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1st April 2010 to the end of the POI, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.

Procedure

15. The review covers all aspects of Notification No. 14/08/2008-DGAD dated the 1st October, 2009 (final findings of the original investigation).

16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject countries, the government of the subject country(ies) through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240 Udyog Bhawan,
New Delhi.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

19. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis.

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority